मुख्यमंत्री कल 45 अहम मुद्दों पर करेंगे समीक्षा बैठक, मंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव 14 मई को मंत्रालय में राज्य सरकार के 45 महत्वपूर्ण मुद्दों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। यह बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें मंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। बैठक में ग्रामीण और शहरी विकास, पेयजल, धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री जिन प्रमुख मुद्दों की समीक्षा करेंगे, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि की मुफ्त रजिस्ट्री अभियान, ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था, नर्मदा समग्र मिशन, राम वन पथगमन और कृष्ण पाथेय परियोजना, महाकाल मंदिर की तर्ज पर अन्य मंदिरों में होमगार्ड व्यवस्था, प्रदेश में नए एयरपोर्ट विस्तार, अग्निवीरों को आरक्षण और मंत्रालय में बायोमैट्रिक उपस्थिति जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मित्र पार्क और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास आईटीआई संस्थानों को रोजगार से जोड़ने पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार का फोकस योजनाओं की प्रगति और जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति जानने पर रहेगा।

21 मई से विभागवार समीक्षा- मुख्यमंत्री 17 मई को मंत्रियों के साथ वन-टू-वन बैठक करेंगे। इसके बाद 21 मई से विभागवार समीक्षा बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों में संबंधित मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण विभागों को अपनी प्रस्तुति के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, ताकि योजनाओं की स्थिति और नई प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा हो सके। इन बैठकों में विभागों की नई योजनाओं, पुरानी योजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाने और लंबित मामलों में तेजी लाना बताया जा रहा है।

कैबिनेट विस्तार और बदलाव की अटकलें - मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों के साथ मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं भी तेज हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार कुछ मंत्रियों के कामकाज और प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है। राजनीतिक स्तर पर यह भी चर्चा है कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। वहीं, विवाद में रहने वाले मंत्रियों को हटाया जा सकता है। हालांकि सरकार या संगठन की ओर से अभी तक किसी संभावित फेरबदल को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं।

नीट-यूजी पेपर लीक में एमपी कनेक्शन!

सीहोर की यूनिवर्सिटी का नाम आते ही मचा बवाल

सीहोर। देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 में कथित पेपर लीक का दाग अब मध्य प्रदेश के सीहोर तक पहुंच गया है। लाखों छात्रों के सपनों को झकझोर देने वाले इस सनसनीखेज मामले में राजस्थान पुलिस ने महाराष्ट्र के नाशिक से एक आरोपी छात्र शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी का संबंध सीहोर स्थित श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी से रहा है। इस खुलासे के बाद शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है और पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

–नाशिक से गिरफ्तारी, राजस्थान पुलिस की कड़ी पूछताछ

नीट पेपर लीक की परतें खुलने के साथ राजस्थान पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। इसी कड़ी में नाशिक निवासी शुभम खैरनार को हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शुभम पर परीक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों और कथित नेटवर्क से संबंध रखने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी किसी बड़े गिरोह का हिस्सा था या फिर केवल एक कड़ी।

सीहोर की सत्यसाई यूनिवर्सिटी से जुड़ाव ने बढ़ाई सनसनी- जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि शुभम खैरनार ने वर्ष 2021 में सीहोर स्थित श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद चिकित्सा यानी बीएएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। यही तथ्य सामने आते ही सीहोर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। स्थानीय स्तर पर सवाल उठने लगे कि क्या आरोपी का विश्वविद्यालय से सक्रिय संपर्क था? क्या उसने यहां किसी नेटवर्क का निर्माण किया? इन सवालों ने पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

'प्रवेश लिया, लेकिन कभी विश्वविद्यालय नहीं आया'- मामले को तूल पकड़ता देख विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल सफाई दी है। कुलगुरु मुकेश तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शुभम खैरनार ने प्रवेश तो लिया था, लेकिन उसके बाद वह कभी विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि शुभम की किसी परीक्षा में उपस्थिति दर्ज नहीं हुई और न ही उसने किसी शैक्षणिक गतिविधि में हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने खुद को इस पूरे मामले से अलग बताते हुए जांच एजेंसियों को हरसंभव सहयोग देने की बात कही है।

22 लाख छात्रों के सपनों पर संकट – जानकारी के अनुसार, नीट-यूजी 2026 परीक्षा में इस वर्ष 22 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। डॉक्टर बनने का सपना लेकर महीनों तक कठिन तैयारी करने वाले छात्रों के लिए पेपर लीक की खबर किसी सदमे से कम नहीं रही। परीक्षा रद्द होने की खबर ने देशभर में नाराजगी और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया। अभिभावक और छात्र लगातार निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

सीबीआई जांच से बढ़ा दबाव - मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें किन-किन राज्यों के लोग शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शुभम खैरनार की गिरफ्तारी इस पूरे रैकेट का सिर्फ शुरुआती सिरा हो सकती है। आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम सामने आने की आशंका जताई जा रही है।

शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, छात्रों का टूटा भरोसा- नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में धांधली के आरोपों ने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों छात्रों का भरोसा डगमगा गया है। सीहोर से जुड़े इस कनेक्शन ने स्थानीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों पर टिकी है कि आखिर इस साजिश की असली परतें कब और कैसे सामने आएंगी। देश के करोड़ों लोगों को इंतजार है उस सच का, जो इस हाई-प्रोफाइल शिक्षा घोटाले का पर्दाफाश करेगा।

राष्ट्रीय ईपीएस-95 पेंशनर्स एसोसिएशन की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित

अजय श्रीवास्तव संरक्षक एवं बाजपेई राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त

भोपाल। राष्ट्रीय ईपीएस-95 पेंशनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण वर्मा ने संगठन को मजबूत एवं सक्रिय बनाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों की घोषणा की है। जारी सूची के अनुसार अजय श्रीवास्तव को राष्ट्रीय संरक्षक तथा अनिल बाजपेई को राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। घोषित कार्यकारिणी में अरुण वर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि झारखंड के आलोक रंजन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर ओ.पी. सोनी, पी.सी. जैन (मध्यप्रदेश), अशोक पाटिल (महाराष्ट्र), पूरन सिंह (उत्तराखंड) एवं तानसेन चंदवंशी (छत्तीसगढ़) को नियुक्त किया गया है।राष्ट्रीय महासचिव के रूप में संत स्वरूप तिवारी (मध्यप्रदेश) एवं अनिल सिंह रावत (उत्तरप्रदेश) को दायित्व सौंपा गया है। वहीं एस.सी. त्रिपाठी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। संगठन को विस्तार देने हेतु आर.के. श्रीवास्तव, पी.एल. शर्मा, हतिम अली अंसारी एवं वाय.पी.एस. घोरपड़े को राष्ट्रीय संगठन सचिव नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आर.एस. रघुवंशी (मध्यप्रदेश), जगदीश राउत (बिहार), अनिल हिम्सल (महाराष्ट्र) एवं पूरन सिंह (छत्तीसगढ़) को शामिल किया गया है। महिला प्रकोष्ठ में मंजू भोजवानी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, वीणा जोशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इग्निस फ्रांसिस को राष्ट्रीय महासचिव तथा रेखा बाजपेई को संगठन सचिव बनाया गया है। नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद देशभर के कर्मचारी संगठनों एवं पेंशनर्स प्रतिनिधियों ने सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

20 मई को देशभर में दवा दुकानें रहेंगी बंद, ऑनलाइन फार्मेसी सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन

इंदौर। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने 20 मई को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है। संगठन ने अवैध ई-फार्मेसी और ज्यादा डिस्काउंट के मामले में सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। फार्मेसी और केमिस्ट सेक्टर से जुड़े देशभर के करीब 12.40 लाख दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ विरोध में शामिल होने की घोषणा की है।ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स दवा विक्रेताओं का एक शीर्ष संगठन है, जो देशभर के करीब 12.40 लाख से अधिक दवा विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस संगठन ने ई-फार्मेसी के मामले में सरकार की अनदेखी के खिलाफ 20 मई 2026 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की है। संगठन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि बार-बार के अनुरोधों के बावजूद दवा व्यापार की गंभीर समस्याओं पर सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से देशभर के विक्रेताओं में भारी नाराजगी है।एआईओसीडी के अध्यक्ष जे एस शिंदे और महासचिव राजीव सिंघल ने संयुक्त रूप से कहा, यह केवल व्यापार का नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा का मामला है। अगर 20 मई तक सरकार इन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है।

धार में बनेगा आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्सः घंटाघर को मिलेगा नया स्वरूप, 4.95 करोड़ की आएगी लागत

धार । धार शहर में जल्द ही आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। बुंदेलवाड़ी स्थित पुरानी नगर पालिका भवन परिसर में करीब 64 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। लगभग 4 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में दुकानों के साथ पुराने घंटाघर का भी रिनोवेशन किया जाएगा। स्टेटकालीन घंटाघर को नई पहचान देने के लिए लाल पत्थर, मार्बल और ग्रेनाइट से संवारा जाएगा।टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले मंगलवार को नपा अध्यक्ष नेहा बोडाने, महेश बोडाने, उपाध्यक्ष मयंक म्हाले, सीएमओ वी.के. सिंह सहित पार्षदों ने भूमिपूजन किया। नपा अध्यक्ष ने निर्माण एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

सीएमओ विश्वनाथ सिंह ने बताया कि कॉम्प्लेक्स बनने से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही शहर की सुंदरता और सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। नागरिकों को एक ही स्थान पर व्यवस्थित बाजार की सुविधा मिल सकेगी। डीपीआर के अनुसार घंटाघर के चारों ओर 64 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। आम लोगों की सुविधा के लिए कॉम्प्लेक्स में दो निकासी द्वार बनाए जाएंगे। परिसर में पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी, ताकि लोग आसानी से वाहन खड़े कर खरीदारी कर सकें।

सबसे अनूठा नेशनल हाईवे, 15 साल में दो कांट्रेक्टर ने हाथ खड़े किए, अब एनएचआईए खुद बनाएगा

सिंगरौली। एक ऐसा नेशनल हाईवे, जिसे बनाने में केंद्र सरकार को भी पसीना आ गया। ये हाईवे 15 वर्षों से बन रहा है। ये हाईवे सेंसर में भी गूंजा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस हाईवे को लेकर कहा था कि इस पर किताब लिखी जा सकती है। 15 साल से बन रहे हाईवे का टेंडर दो बार हो चुके हैं। दोनों कंपनियों ने इस हाईवे को बनाने से हाथ खड़े कर दिए। कंपनियां काम छोड़कर चली गईं। अब तीसरी बार खुद एनएचआईए ने इस सड़क को बनाने की जिम्मेदारी ली है। अब लोगों में आस जगी है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 39 है, जो सिंगरौली से सीधी को जोड़ता है।सिंगरौली और सीधी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 का निर्माण कार्य 2010 में शुरू हुआ था। पहले एक कंपनी को इसका टेंडर मिला और कुछ सालों तक उसने काम किया और फिर अधूरा छोड़कर चली गई। संसद में मुद्दा बार-बार गूंजा, फिर दोबारा टेंडर किया गया लेकिन दूसरी कंपनी ने भी कुछ दिन बाद हाथ खड़े कर लिए। यह देश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसके लिए 3 बार टेंडर हुए लेकिन काम कब पूरा होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।15 साल बाद भी सीधी व सिंगरौली के लोगों का नेशनल हाईवे पर चलने का सपना भी अधूरा है। फिलहाल सीधी-सिंगरौली के नेशनल हाईवे 39 पर चलना बड़ा जोखिम भरा है। 15 वर्षों से अधूरे निर्माण कार्य के कारण नेशनल हाईवे 39 की स्थिति कुछ इस कदर हो चुकी है कि आम लोगों को सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं। कई जगहों पर पुलिया निर्माण नहीं होने के कारण घंटों जाम लग जाता है। बीच-बीच में कुछ जगहों पर सड़क का निर्माण कार्य हुआ है। बारिश के दौरान यह सड़क इतनी खतरनाक हो जाती है कि इस पर बाइक सवार को भी जान जोखिम में डालकर चलना पड़ता है।सीधी सांसद राजेश मिश्रा ने बताया हमने पूरा प्रयास करके एमपीआरडीसी से काम को एनएचआईए को ट्रांसफर कराया। वर्क ऑर्डर हो गया है। काम भी शुरू हो गया है। मैं सांसद होने के नाते इस रोड में जो देरी हुई है क्षेत्रवासियों से व्यक्तिगत तौर पर क्षमा चाहूंगा। इस सड़क के निर्माण कार्य की रोजाना मॉनिटरिंग करूंगा। क्षेत्रवासियों को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि नियत समय 2 वर्ष में इस सड़क का कार्य पूरा होगा और लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात मिलेगी।

मध्य प्रदेश में खाद की टेंशन!

पर्याप्त स्टॉक के दावों के बाद किसान हो रहे परेशान

भोपाल। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही अभी सीजफायर हुआ है लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमोनिया और सल्फर की आपूर्ति प्रभावित होने से खाद की कमी महसूस की जा रही है। यूरिया की कीमत तेजी से बढ़ रही हैं और लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। देश के साथ मध्य प्रदेश में भी वर्तमान स्थिति में फर्टिलाइजर के वितरण में कमी आई है। हालांकि केन्द्र और राज्य सरकारें स्थिति को संभालने का दावा जरूर कर रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, रीवा, सतना, पन्ना और टीकमगढ़ समेत दर्जनों जिलों में खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। किसान परेशान हो रहे हैं। किसान खाद की कालाबाजारी की लगातार शिकायत कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन जमाखोरों रोकने के लिए निगरानी कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत, पर्याप्त स्टॉक का दावा- केन्द्र और राज्य सरकार ने दावा किया है कि खरीफ 2026 के लिए खाद का स्टॉक पर्याप्त है लेकिन सप्लाई चेन में बाधा के कारण जमीनी स्तर पर किल्लत दिख रही है। सरकार किसानों को यूरिया के बजाय नैनो यूरिया और अन्य विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है।अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बावजूद सप्लाई चेन टूटने से देश के साथ मध्य प्रदेश में भी खाद की किल्लत हो रही है। अधिकांश जिलों में खाद वितरण केन्द्रों में टोकन होने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। हालांकि सरकार सब्सिडी के जरिए स्थिति को नियंत्रित करने के दावे जरूर कर रही है लेकिन खाद के लिए किसानों की लाइनें बता रही हैं कि प्रदेश में फर्टिलाइजर्स की कमी बनी हुई है।

मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन 2026 के लिए खाद की जरुरत- मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन 2026 के लिए कृषि विभाग ने उर्वरकों की कुल जरुरत लगभग 390.54 लाख मीट्रिक टन (राष्ट्रीय स्तर पर) का आंकलन किया है. जिसमें राज्य के लिए भी पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया गया है. प्रदेश में खरीफ फसलों सोयाबीन, मक्का और धान के लिए किसानों को फर्टिलाइजर्स की जरुरत है.

यूरिया: लगभग 7.25 लाख मीट्रिक टन
डी.ए.पी : लगभग 3.00 लाख मीट्रिक टन
एन.पी.के: लगभग 2.50 लाख मीट्रिक टन
एस.एस.पी: लगभग 2.00 लाख मीट्रिक टन
एम.ओ.पी : लगभग 0.80 लाख मीट्रिक टन

खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में 51 प्रतिशत से अधिक खाद का स्टॉक पहले से ही मौजूद है और सरकार ने अतिरिक्त 97 लाख मीट्रिक टन खाद का इंतजाम किया है ताकि किसानों को परेशानी न हो। केन्द्र सरकार का दावा है कि सामान्यतः 33प्रतिशत खाद का स्टॉक रहता है लेकिन यह फिलहाल 51 प्रतिशत से अधिक है।

खरीफ सीजन के लिए खाद का स्टॉक

प्रदेश के कृषि अधिकारियों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन 2026 की बोवनी के लिए खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। राज्य के विभिन्न जिलों में यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया गया है। मई 2026 की स्थिति में यूरिया का लगभग 5627 मीट्रिक टन, डीएपी लगभग 2393 मीट्रिक टन, एनपीके लगभग 9986 मीट्रिक टन, एसएसपी लगभग 9281 मीट्रिक टन खाद का स्टॉक उपलब्ध है।

प्रदेश में खाद की उपलब्धता (मई 2026 की स्थिति में)

यूरिया- लगभग 5627 मीट्रिक टन
डीएपी - लगभग 2393 मीट्रिक टन
एनपीके -लगभग 9986 मीट्रिक टन
एसएसपी : लगभग 9281 मीट्रिक टन

खाद वितरण के लिए ई-टोकन व्यवस्था- मध्य प्रदेश सरकार ने खाद वितरण के लिए ई-टोकन व्यवस्था लागू है, जिससे लंबी लाइनों से राहत मिली है। 15 जून के बाद यूरिया की 100प्रतिशत आवश्यकता पूरी की जाएगी, जबकि अन्य खाद का वितरण शुरू हो चुका है। किसान ई-विपणन पोर्टल पर सोसायटी या निजी दुकानों के माध्यम से खाद की बुकिंग कर सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। किसान खाद की भारी किल्लत और 275 रुपये की खाद कालाबाजारी के बाद 600 रुपए तक में खरीदने को मजबूर हैं। सरकार ने यूरिया के लिए 50प्रतिशत की बाध्यता खत्म कर दी है और टोकन व्यवस्था के तहत एक क्लिक पर यूरिया उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। पुलिस और प्रशासन जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी कर रहे हैं।मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किसानों से जरुरत के अनुसार खाद का उपयोग करने और कालाबाजारी करने वालों की शिकायत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद का पर्याप्त स्टॉक है और किसानों को पैनिक होकर ब्लैक में खाद खरीदने की जरुरत नहीं है।कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल का कहना है, प्रदेश में पर्याप्त खाद उपलब्ध है, किसानों को खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। कालाबाजारी और जमाखोरी को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

होर्मुज जलमार्ग में तनावपूर्ण हालात का असर- अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर अब वैश्विक सप्लाई चेन पर साफ दिखाई देने लगा है। खासकर होर्मुज जलमार्ग में तनावपूर्ण हालात के चलते तेल और गैस की आवाजाही काफी हद तक प्रभावित हुई है। यह वही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कई देशों के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा और कच्चे माल का परिवहन होता है।जिसका सीधा प्रभाव भारत के फर्टिलाइजर उत्पादन पर भी पड़ा है।

नहीं बढ़ेंगी खाद की कीमतें- केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में ग्वालियर दौरे के दौरान कहा था कि युद्ध की वजह से अभी रासायनिक खाद का कोई संकट नहीं है। देश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। केन्द्र सरकार अलग-अलग स्तर पर इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया में पैदा हुई परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार बैठकें की जा रही हैं।

मध्य प्रदेश में खाद के पर्याप्त स्टॉक का दावा - शिवराज सिंह ने कहा युद्ध के चलते कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। इससे डीएपी और यूरिया के रेट में बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन सरकार ने तय किया है कि डीएपी और यूरिया के दाम पहले के तरह ही रहेंगे। खाद की कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी। इसके लिए केन्द्र सरकार ने अपनी पिछली कैबिनेट बैठक में 41 हजार करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की है ताकि बढ़ती कीमतों का बोझ किसानों पर न पड़े। इसके अलावा खाद की उपलब्धता जहां से हो सकती है, उसके प्रयास किए जा रहे हैं।शिवराज सिंह ने कहा कि मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई परेशानी है ही नहीं है, जाहिर है कि संकट तो है, लेकिन संकट से निपटने के लिए हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिन और रात कोशिश कर रहे हैं कि जनता और किसानों पर इसका असर ना पड़े।

57 लाख टन यूरिया और अन्य उर्वरक आयात के लिए टेंडर जारी- नई दिल्ली में उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस.शर्मा ने 4 मई 2026 को जारी किए आंकड़ों में बताया कि उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 62 लाख मीट्रिक टन से अधिक पहुंच गया है। जबकि, आयात लगभग 15 लाख मीट्रिक टन है। इसके साथ ही देश में वर्तमान अवधि के लिए उर्वरक का कुल स्टॉक लगभग 78 लाख मीट्रिक टन हो गया है। उन्होंने बताया कि 38 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 19 लाख मीट्रिक टन फॉस्फेटिक और पोटेशियम युक्त उर्वरकों की खरीद के लिए वैश्विक टेंडर जारी किए गए हैं। यानी 57 लाख मीट्रिक टन उर्वरक विदेशों से मंगाई जा रही है। इस हिसाब से 78 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की गई और 57 लाख मीट्रिक टन मंगाई जा रही उर्वरक को जोड़ दें तो 135 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का स्टॉक बैठता है देश के उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने एक प्रेस ब्रीफिंग में 11 मई को देश के खाद भंडार का पूरा ब्यौरा पेश किया है। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और स्टॉक की निगरानी कर रही हैं। भारत के पास पर्याप्त उर्वरक भंडार है और पश्चिमी एशिया की स्थिति का घरेलू आपूर्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। खरीफ सीजन के लिए मांग की तुलना में 51प्रतिशत से अधिक का रिकॉर्ड स्टॉक पहले से उपलब्ध है। घरेलू उत्पादन के साथ-साथ सरकार ने बड़े पैमाने पर आयात के सौदे भी पक्के कर लिए हैं ताकि 15-20 दिनों में शुरू होने वाले पीक सीजन में कोई दिक्कत न आए।

देश में खाद का भंडार
(4 मई तक की स्थिति)

यूरिया- 74.48 लाख मीट्रिक टन
डीएपी - 22.47 लाख मीट्रिक टन
एनपीके - 59.53 लाख मीट्रिक टन
एसएसपी -26.71 लाख मीट्रिक टन
एमओपी- 12.52 लाख मीट्रिक टन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की किसानों से अपील- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रासायनिक उर्वरकों के जरुरत से ज्यादा इस्तेमाल को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने 11 मई 2026 को तेलंगाना में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से किसानों से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50 प्रतिशत तक कटौती करने की अपील की है। उन्होंने धरती मां के संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा, यूरिया समेत कई फर्टिलाइजर का भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है और इसके चलते विदेशी मुद्रा का उपयोग होता है और उसे डॉलर में ये रकम चुकानी होती है।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रासायनिक खाद को लेकर कही गई मुख्य बातें

पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि रसायनों के ज्यादा इस्तेमाल से धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है और जमीन बंजर हो रही है।

किसानों से यूरिया और अन्य रासायनिक खादों का इस्तेमाल 50प्रतिशत तक कम करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है।

यूरिया और अन्य फर्टिलाइजर को भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। इसमें विदेशी मुद्रा की बड़ी संख्या में खपत होती है।

खेती की लागत कम करने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया।

रासायनिक उर्वरकों के बजाय वैकल्पिक और किफायती उर्वरक खादों के इस्तेमाल की सलाह दी।

जैसे शरीर के लिए दवा की सही मात्रा जरूरी है, वैसे ही मिट्टी के लिए सही मात्रा में खाद जरूरी है।